(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन रेजिन-आधारित उद्योगों को बचाने के लिये कौन-कौन से कदम उठा रही है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) वित्त मंत्रालय को ओलियो पाइन रेजिन के उत्पादकों से इस आशय के अभ्यावेदन मिलते रहे है, कि इस मद पर सीमाशुल्क बढ़ाया जाए और प्रतिकारी शुल्क लगाया जाए, जिससे घरेलू उत्पादकों को यथेष्ट संरक्षण मिल सके। दूसरी ओर, उक्त रेजिन पर प्रयोक्ता उद्योग उस पर सीमा-शुल्क समाप्त किये जाने के पक्ष में है। इस संबंध में प्राप्त सभी अभ्यावेदनों को मद्देनजर रखते हुए 1995 के बजट में ओलियो पाइन रेजिन पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। किन्तु, उत्पाद शुल्क में इस वर्ष के बजट में कोई परिवर्तन किए बिना पूरी छूट जारी रखी गई। इस समय ओलियो पाइन रेजिन पर आयात शुल्क में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

Entry of MNCs in consumer Goods Sector

6752. DR. B. B. DUTTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have allowed entry of Multinational Corporations in consumer goods sector including fast food items;

(b) if so, the details thereof?

(c) the reasons for allowing multinationals to enter into this sector;

(d) whether Government has assessed impact of MNC entry in this sector; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (d) Government has allowed foreign companies including multinational companies for production of varous items including some fast food items. These *inter-alia* include breakfast cereals, soft drinks, chocolates, coca products, mushrooms and pizzas. Multinationals have been allowed to enter this sector keeping in view the reqirement for investment in this area, potential for employment generation and the need for expending the domestic and foreign market.

(e) Government's policy has ensured that the bulk of foreign investment is directed towards the core sectors. Some investment inevitably, will be directed towards the consumer goods sector, but it is not likely to affect domestic industry. On the other hand it will create jobs and employment opportunities, bring new technology, provide some competition to domestic industry and promote competition and efficiency.

नरम चमड़े पर आयात-शुल्क कम किया जाना

6753. **प्रो० राम बक्श सिंह वर्मा**: क्या **वाणिज्य** मंत्री 20 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 870 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने नरम चमड़े (साफ्ट लेदर) के आयात पर आयात-शुल्क कम करने के किसी प्रस्ताव पर निर्णय लिया है, जैसाकि निर्यातकों द्वारा मांग की गई है; और